



केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

प्रलिस के लयः

दल्लऱ वशऱष पुलसऱ प्रतषऱठान (DSPE) अधनऱनऱडड, डुरषुठऱऒऱर नवलरण अधनऱनऱडड, डुरषुठऱऒऱर नवलरण पर संथऱनड सडतऱऱ

डेनुस के लयः

CBI और सडऱरशऱँ से संबंघतऱ डुदुडे

ऒरऒऱ डें कुडँ?

ऒऱरडुडऱ, लुक शऒऱडडत, ऒऱनुन और नुडऱडड संबंघुी संसदुीड सडतऱऱ ने ऒई रऱऒुडँ दुवलरऱ CBI ऒऱँऒ हेतु सऱडऱनुड सडडतऱ वऱडस लडड डऱने के डदुडेनऒर ऒडऱ हे ऒ CBI कु नडुतऱरतऱ ऒरने वऱले डुँऒुदऱ ऒऱनुन कुी 'ऒई सीडऱरुँ' हैं और इसऒुी सुथतऱऱ, ऒऱरुडँ एवं शऒुतडुीँ कु परडऱषतऱ ऒरने के लडड इसे एक नऱ ऒऱनुन के सऱथ डदलने कुी ऱवशुडडऒतऱ हे ।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI):

डरऒऱडडः

- CBI कुी सथऱडनऱ वरुष 1963 डें हुई थुी और डह दल्लऱ वशऱष पुलसऱ प्रतषऱठऱन (Delhi Special Police Establishment- DSPE) अधनऱनऱडड दुवलरऱ शऱसतऱ हे ।
 - इसऒुी सथऱडनऱ डुरषुठऱऒऱर नवलरण पर संथऱनड सडतऱऱ (1962-1964) के सुऒुडऱवुँ पर कुी गई थुी ।
- वरुतडऱन डें CBI डऱरत सरऒऱर के ऒऱरडुडऱ वडडऱग, ऒऱरडुडऱ, डेंशन और लुक शऒऱडडत डंतुरऱलय के अधुीन ऒऱरुडड ऒरतुी हे ।

ऒऱरुडडः

- डऱरतुीड अधऒऱरऱडुीँ, सऱरुवऒनऒऱ कुषेतर के उडऒऒरडुँ, नऱगऱडुँ और डऱरत सरऒऱर के सुवऱडतऱतुव डऱ नडुतऱरण वऱले नऒऱरुडुँ के खलऱडऱ डुरषुठऱऒऱर नवलरण अधनऱनऱडड के तहत केंदुर सरऒऱर के ऒरडुडऱऒऱरऱडुीँ के डुरषुठऱऒऱर, रशऱवतखुीरुी तथऱ दुरुवुडडवऱर के डऱडलुँ कुी ऒऱँऒ ऒरनऱ ।
- रऱऒऒुषुीड और ऱरुथऒऱऒऱ ऒऱनुनुँ के उलुलंघन से संबंघतऱ डऱडलुँ कुी ऒऱँऒ ऒरनऱ, ऱरुथऱतु नरऱडडत एवं ऱडडऱत नडुतऱरण, सीडऱ शुलुऒ तथऱ केंदुरीड उतुडऱद शुलुऒ, ऱडडऒर वदऱशुी डुदुरऱ नडडडुँ से संबंघतऱ ऒऱनुनुँ ऒऱ उलुलंघन ।

- उदऱहरणः नऒलुी डऱरतुीड ऒररुँसी नुडुत, डैऒ डुुखऱधऒुी, ऱडडऱत-नरऱडडत और वदऱशुी डुदुरऱ उलुलंघन ऱदऱऱ ।

डुदुडेः

◦ CBI डनऱड रऱऒुडड पुलसऱः

- ऒसुी वशऱष रऱऒुडड डें CBI ऒऱँऒ रऱऒुडड सरऒऱर दुवलरऱ ऱनुडुडन के अधुीन हे ।
- एक रऱऒुडड डें सतुतऱरुदुद दल ऒडुी-ऒडुी वऱसुतवऒऱऒऱ रूड से और ऒई डऱर ऒडुुडर ऱडडऱर पर CBI कुी डऱडलुँ कुी ऒऱँऒ ऒरने कुी ऱनुडतऱदऱने से इनऒऱर ऒर देतऱ हे, ऒसऱसे ऒऱँऒ कुी सीडऱ सीडडतऱ हुे ऒऱतुी हे ।

◦ ऱुवरलुैडडऱ/दुहरऱवः

- रऱऒुडड पुलसऱ डलुँ के सऱथ वशऱष पुलसऱ प्रतषऱठऱन (CBI ऒऱ एक डुरडऱग) कुे उन ऱडरऱधुँ के लडड ऒऱँऒ और ऱडडडुीऒन कुी सडडवरुतुी शऒुतडुीँ डुरऱडुत हैं ऒुे ऒडुी-ऒडुी डऱडलुँ के दुहरऱव एवं ऱुवरलुैडडऱ ऒऱ ऒऱरण डनते हैं ।

डऱऒनुीतऒऱऒऱ हसुतऒऒुषेडः

- **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने CBI के कामकाज में अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप की आलोचना की है तथा इसे "अपने मालिक की आवाज़ में बोलने वाला पजिरे में बंद तोता" कहा है।

संसदीय समिति के नषिकर्ष और सफ़ारशें:

■ नषिकर्ष:

◦ सामान्य सहमति की वापसी:

- 9 राज्यों ने CBI द्वारा किसी भी जाँच के लिये आवश्यक **सामान्य सहमति को वापस** ले लिया है, जिससे CBI को नषितरति करने वाला मौजूदा कानून अप्रभावी हो गया है।

◦ रकित पद:

- **CBI में रकितियों को आवश्यक गति से नहीं भरा जा रहा है**, जिससे जाँच की गुणवत्ता में बाधा आ रही है जिससे अंततः एजेंसी की प्रभावशीलता एवं दक्षता प्रभावित हो रही है।
- CBI में स्वीकृत 7,295 पदों के मुकाबले कुल 1,709 पद खाली हैं।

- उच्च पदों, कानूनी अधिकारियों एवं तकनीकी अधिकारियों के संवर्गों में **ये रकितियाँ नषिविवाद रूप से मामलों की लंबितता को बढ़ाएगी, जाँच की गुणवत्ता को बाधित करेगी** जो अंततः एजेंसी की प्रभावशीलता एवं दक्षता को प्रभावित करेगी।

■ अनुशंसा:

◦ CBI की स्थिति को पुनः परभाषित करना:

- समिति **CBI की स्थिति, कार्यों और शक्तियों को परभाषित करने** तथा इसके कामकाज में नषिपक्षता सुनषिचति करने के लिये सुरक्षा उपाय नषिधारति करने हेतु एक नया कानून बनाने की सफ़ारश करती है।

◦ रकितियों को तमिही आधार पर भरना:

- समिति **CBI नषिदेशक से सफ़ारश करती है कि वह तमिही आधार पर रकितियों को भरने में हुई प्रगत की समीक्षा करें** और यह सुनषिचति करने के लिये आवश्यक उपाय करें कि संगठन में पर्याप्त स्टाफ है।

◦ प्रतनियुक्त पर नषिभरता को कम करना:

- CBI को **प्रतनियुक्त पर अपनी नषिभरता को कम करना चाहिये** एवं पुलसि नषिरीक्षक तथा पुलसि उपाधीक्षक के पद पर स्थायी कर्मचारियों की भरती करने का प्रयास करना चाहिये।

◦ वाद प्रबंधन प्रणाली: CBI को एक वाद प्रबंधन प्रणाली (Case Management System) नषिमति करनी चाहिये जो एक केंद्रीकृत डेटाबेस होगा, जिसमें इसके पास दर्ज शकियातों एवं उनके नषिटारे में हुई प्रगत का वषिरण होगा।

- पारदर्शता और जवाबदेही सुनषिचति करने के लिये **मामलों के आँकड़े तथा वार्षिक रषिपोर्ट** भी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशति करनी चाहिये।
- CBI के पास दर्ज मामलों का वषिरण, उनकी जाँच में हुई प्रगत और अंतमि परणाम **सार्वजनिक डोमेन** में उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

UPSC सवलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. एक राज्य-वषिष के अंदर प्रथम सूचना रषिपोर्ट दायर करने और जाँच करने के केंद्रीय अनूवेषण ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र पर कई राज्यों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। हालाँकि सी.बी.आई. जाँच के लिये राज्यों द्वारा दी गई सहमति रोके रखने की शक्ति आत्यंतिक नहीं है। भारत के संघीय ढाँचे के वषिष संदर्भ में व्याख्या कीजिये। (2021)

स्रोत: द हद्रि

